Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 05 भाग 03, (अगस्त, 2025)
पृष्ठ संख्या 72–74

हरित क्रांति का आशय

अमिता मीणा,
सहायक प्राध्यापक,
कृषि विज्ञान संकाय,
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ, राजस्थान, भारत।

Email Id: – amitameenaagro@gmail.com

हरिण क्रांति एक ऐसी क्रांतिकारी घटना थी, जिसने भारत की कृषि प्रणाली को बिल्कुल बदल दिया। यह क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई जब देश में खाद्यान्न संकट था और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। हरित क्रांति ने भारत को भूखमरी से बचाया और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया।

नहरी सिंचाई पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया, हरित क्रांति, भारत की कृषि में गतिशील परिवर्तन लाने का लक्ष्य है।

यही कारण है कि इसे बीज–उर्वरक–सिंचाई प्रोद्यौगिकी भी कहा जाता है। अमेरिकी नागरिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन इसका श्रेय देते हैं।

1966 ई. के सूखे के बाद भारत में कृषि विकास की नई प्रणाली की जरूरत पड़ी थी । इस क्षेत्र में पहले से ही कुछ प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन 1966–67 में पंजाब व हरियाणा में इसे पूरी तरह से लागू किया गया. 1951–61 के दशक में 17 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, वहीं 1966–76 के दशक में 49 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जिससे भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसलिए इसका नाम हरित क्रांति था।

महत्वपूर्ण कारक

- भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना।
- गेहूं और धान का उत्पादन कई गुना बढ़ा।
- किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
- विज्ञान आधारित कृषि तकनीक ।
- सेवाओं का विशेष पैकेज ।
- सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज ।

हरित क्रांति का लक्ष्य था कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, जिसमें वह काफी हद तक सफल रहा।

हरित क्रांति का आलोचनात्मक विश्लेषणः

भारत ने हरित क्रांति के बाद कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल की है और अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति और निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। लेकिन हरित क्रांति के अवैज्ञानिक विसरण और प्रयोग से कुछ बुरे परिणाम भी हुए।

विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न

1. हरित क्रांति ने देश भर में विकास की असमानता पैदा की। उदाहरण के लिए, बिहार और ओडिशा पिछड़े रहे, जबकि

पंजाब और हरियाणा विकसित क्षेत्रों में हरित क्रांति से प्रभावित हुए।

2. सिंचित और असिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता में भिन्नता के कारण किसानों के बीच संघर्ष बढ़ा है। साथ ही हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ बड़े किसानों ने उठाया है, छोटे किसानों ने इससे कम लाभ उठाया है।
3. इससे सभी फसलें लाभान्वित नहीं हुईं। गेहूँ और चावल की उत्पादकता को बढ़ाने में ही मुख्य लाभ हुआ है। नकदी, दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई।
4. हरित क्रांति के क्षेत्रों में मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या, नाइट्रोजनी विषाक्तता की समस्या, भूमिगत जलस्तर में कमी की समस्या सहित कई पारिस्थितिक समस्याएं पैदा हुई हैं जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती हैं।

हरित क्रांति का द्वितीय चरण:

1987 के सूखे के असर और खाद्य उत्पादन में गिरावट जैसे कारक को देखते हुए सातवीं योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि हरित क्रांति के दूसरे चरण की जरूरत है।

इस काम के लिए 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया था, जहाँ पहले से ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थीं लेकिन कृषि विकास का गतिमान प्रयास नहीं हुआ था।

द्वितीय चरण में हरित क्रांति के विसरण चरों पर अधिक ध्यान दिया गयाय यानी, हरित क्रांति के प्रभाव को पूर्वी, पठारी और तटवर्ती भारत में फैलाने का फैसला किया गया। चावल की प्राथमिकता दूसरी विशेषता थी।

169 जिलों में से 109 जिलों को चावल की खेती के लिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि पूर्वी भारत और तटवर्ती भारत इसके लिए अनुकूल थे और इसके सकर बीज भी उपलब्ध थे, बस किसानों को शिक्षित करना था।

तिलहन और दलहन की वृद्धि तीसरी विशेषता थी। इसके लिए पठारी भारत को प्रधानता दी गई और तकनीकी मिशन बनाए गए और ड्रिप सिंचाई योजना बनाई गई।

हरित क्रांति के द्वितीय चरण में

1. सिंचाई के लिए भूमिगत जल के प्रयोग पर दबाव दिया गया
2. संकर बीज व उर्वरकों के छोटे पैकेटों की उपलब्धता करवाना
3. कीटनाशकों पर उत्पाद कर की छूट करवाना

ग्रीष्म क्रांति के द्वितीय चरण में, कीटनाशकों के प्रयोग पर पहली बार दबाव डाला गया क्योंकि ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु के हैं, जहाँ कीटपतंगों का प्रचलन अधिक होता है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण अधिक वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण है और इसमें पहले हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के साथ–साथ उनके पुनर्निर्माण को भी रोका गया है।

ताकि कृषि उत्पादन में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो सके, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा कृषि के पोषणीय विकास पर आधारित है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एक द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत बताई थी, जिसमें मिट् टी से विपणन तक हर क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए था।

किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने एक व्याख्यान में कहा कि हरित क्रांति की सफलता के बाद अब सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़ना होगा ताकि देश का खाद्य उत्पादन 210 मीट्रिक टन से 420 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सके। '

इसके लिए निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है:

1. मृदा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भौतिक और जेविक सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता अनिवार्य है। इसलिए रासायनिक के अलावा जैविक और कम्पोस्ट खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
2. शुष्क कृषि द्वारा बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्षा आधारित क्षेत्रों में टिकाऊ जल संरक्षण प्रणाली बनाने की जरूरत है, जहाँ सिंचाई व्यवस्था नहीं है।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल के प्रभावी उपयोग के लिए ग्रामसभाओं को ''जल पंचायतों'' में बदलना आवश्यक है।
4. भारतीय कृषि में संस्थागत समस्याओं में से अधिकांश भूमि सुधार की दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है ताकि कृषि निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए छोटे और सीमांत किसानों को कृषि विकास के लिए आवश्यक सहायता देना होगा और ऋण सुधारों की दिशा में भी सकारात्मक पहल करनी होगी।
5. कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ–साथ खेतों में और खेत से बाहर वैकल्पिक रोजगार (काम के बदले अनाज, डळछत्म्ळ।) जैसे रोजगार कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए।
6. लघु खेत प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि छोटे कृषि क्षेत्र के बावजूद अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने और कम निवेश से अधिक आय प्राप्त करने के नवीन उपायों का उपयोग करने के लिए लघु खेत प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

   इस उद्देश्य से, किसान बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड उनकी मदद कर सकते हैं । कृषि में उत्पादन लागत बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ना चाहिए।
7. कृषि को भी उद्योगों की तरह सुविधाएँ मिलीं। उन्हें बाजार से जोड़ा जाए। संविदा कृषि (ब्वदजतंबज थ्ंतउपदह) और कृषि आर्थिक क्षेत्र (।म्) इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने फसलोपरांत तकनीकी, कृषि प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्रों में कम से कम 60,000 ''प्रयोगशाला से खेत तक'' प्रदर्शन कार्यक्रमों की जरूरत पर बल दिया है ताकि पोषणीय कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके और उद्योगों को निरंतर कृषिगत कच्चा माल उपलब्ध हो सके।

स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय में ''द्वितीय हरित क्रांति'' की ओर प्रस्थान किया गया है, जिसे ''सदाबहार हरित क्रांति'' भी कहा जाता है. तीनों राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्तरों पर।

इसमें कृषि जलवायु प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास और विविधीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, ताकि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।